

जमशेदपुर का टाटा स्टील पॉचवें स्थान पर है जबकि जिंदाल स्टील एण्ड पावर ऑफ रायगढ़ नौवें स्थान पर है। एसएआईएल संयंत्रों में से केवल राउरकेला के एक संयंत्र ने कुछ परिणाम दिखाएँ। अन्य चार संयंत्र – भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, और बर्नपुर – ने स्वेच्छा से कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं किया गया (संलग्न पत्रक देखें)।

अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र की 6.6 गीगाकैलोरी प्रति टन ऊर्जा की खपत वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।
2. विद्युत उत्पादन, टाउनशिप और अन्य डाउनस्ट्रीम कार्यों को छोड़कर प्रसंस्कृत जल की खपत 3.5 घन मी प्रति टन अधिक है जो वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास से तीन गुनी अधिक है।
3. ऐसा देखा गया है कि विशालकाय संयंत्र अत्यधिक भूमि हानिकारक होते हैं। उनके पास लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि प्रति दस लाख टन स्थापित क्षमता होती है। एक सुव्यवस्थित संयंत्र को 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि इस्पात संयंत्रों की शेष भूमि का अच्छी तरह उपयोग किया गया तो उद्योग 3000 लाख टन से अधिक इस्पात का उत्पादन कर सकता है, जबकि आज यह 750 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है। वास्तव में, इस्पात उद्योग को 2025 तक अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4. ऐसा देखा गया है कि अधिकांश इस्पात संयंत्र प्रदूषण मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।

सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई का कहना है: "इस क्षेत्र का खराब पर्यावरणीय प्रदर्शन देश में नियामक संस्थानों की विफलता का एक कारण है। कोई भी इस क्षेत्र को अपनी हरित आधार रेखा में सुधार करने के लिए नहीं कह रहा है। कोई भी इसके वास्तविक प्रदर्शन की माप और निगरानी नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। देश ने अपनी प्रदूषण नियामक सामग्रियों को नष्ट करने की दिशा में कदम उठाया है – इस्पात क्षेत्र इसका एक कठोर अनुस्मारक है।"

सीएसई के उपमहानिदेशक और हरित मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रमुख चंद्र भूषण इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि "लौह एवं इस्पात क्षेत्र का प्राप्तांक जीआरपी द्वारा पहले कवर किए गए अन्य उद्योगों में से कुछ की तुलना में सबसे कम है। वास्तव में, चौकाने वाली बात तो यह है कि अभूतपूर्व रूप से आठ कंपनियों को किसी भी पुरस्कार के लिए पूरी तरह से अयोग्य पाया गया है। यह इस क्षेत्र के निराशाजनक पर्यावरणीय प्रदर्शन का सूचक है जो एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है।"

enlt Hkj rht m | lsc i ; lKj .k dls /dDk nsrk gS

भारत में उद्योग के समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से सीएसई के हरित मूल्यांकन अभ्यास किस ओर इशारा करते हैं?

सुनीता नारायण का कहना है: "जब हम ने 1990 के मध्य दशक में मूल्यांकन कार्य का आरम्भ किया था उस समय भारतीय उद्योग के पास पर्यावरणीय प्रबंधन के बारे में कोई सुराग नहीं था। उस समय तक हम ने 2005 में सीमेंट क्षेत्र का मूल्यांकन किया, हम ने ध्यान दिया कि भारतीय उद्योग कई मानदंडों पर विश्व स्तर पर सर्वोत्तम के करीब था। पर्यावरण इसमें मुख्यधारा में था।"

उनका कहना है: "लेकिन 2012 में, मुझे लगता है कि हमें इस आकलन को संशोधित करना चाहिए। लौह एवं इस्पात उद्योग का मूल्यांकन, जो कि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके अपने केन्द्रीय मंत्रालय और प्रदर्शन के लिए इसके बिल्कुल अपने प्रधानमंत्री पुरस्कार में सबसे बड़े उद्योग नाम शामिल हैं। और उनके पर्यावरणीय गैर-प्रदर्शन ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकन कार्यक्रम में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों ने भी संयोग से ऐसा ही किया होगा। शीर्ष तीन कंपनियों ने अपनी लागत में कटौती करने के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है – संयोगवश इससे भी उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

चंद्र भूषण के अनुसार, जीआरपी अभ्यास से लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में जो पता चला है वह एक बेढंगे भविष्य की ओर इशारा करता है। तेजी से इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है: एक दशक के भीतर, इसने एक 240 लाख टन वाले उद्योग से अगले दो वर्षों में 700 लाख टन वाले विशालकाय उद्योग का रूप ले लिया है। विस्तार के साथ और अधिक पर्यावरणीय समस्याएँ सामने आएंगी। क्या भारतीय इस्पात निर्माता इनका सामना करने में सक्षम होंगे?

l Mgg /lkrqck D; k fd; k t k l drk gS

निस्संदेह, उम्मीद की एक किरण है।

चंद्र भूषण का कहना है: "इस क्षेत्र की भावी योजना स्पष्ट है। इसे अपने पारिस्थितिक पदचिह्नों में कटौती करनी होगी, अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में निवेश करना होगा और स्थानीय हितधारकों (काफी हद तक, वे समुदाय जो संयंत्रों के आसपास रहते हैं और उनके द्वारा प्रभावित हैं) के साथ बातचीत करना होगा।"

संयंत्रों को भूमि के मामले में कुशल होना पड़ेगा, और केवल उतना ही पानी इस्तेमाल करना होगा जितना बाष्पीकरणीय नुकसान को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्हें अपशिष्ट जल के निर्वहन को बंद करना होगा, और अपने ठोस अपशिष्टों का पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग करना होगा। और उन्हें पलायक उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे।

जीआरपी शोधकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में परिवर्तन की काफी संभावना है, और तकनीकी दृष्टि से इस योजना को प्राप्त किया जा सकता है। नारायण का कहना है: "हमें उम्मीद है कि हमारा मूल्यांकन उस परिवर्तन को संभव बनाने में योगदान करेगा।"

- एक्सेस से संबंधित जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट, www.cseindia.org पर जाएँ
- किसी भी अतिरिक्त विवरण और जानकारी के लिए, कृपया 9910864339 पर सुपर्णो बनर्जी से संपर्क करें या उन्हें souparno@cseindia.org पर ईमेल करें